



मंगोलिया के पश्चिम में गोबी रेगिस्तान में कभी एक फलता-फूलता समृद्ध साम्राज्य था। धार्मिक शिक्षा, कला और व्यापार का केन्द्र रहे इस साम्राज्य के अब सिर्फ अवशेष बचे हैं। खारा खोटो (मंगोलियन भाषा में ब्लैक सिटी) की स्थापना 1032 ईस्वी में हुई थी। यह पश्चिमी शिया राजवंश (1038-1227) की राजधानी था। जल्दी ही यह एक प्रमुख व्यापारिक केन्द्र बन गया। सन् 1226 ईस्वी में इस पर चंगेज खान ने कब्जा कर लिया पर उसने इस शहर को तहस नहस नहीं किया, जैसे कि चंगेज खान की सेना आम तौर पर अन्य शहरों के साथ करती थी। उल्टे यह शहर मंगोल शासन काल में खूब फला फूला। चंगेज खान के पोते, कुबलई खान के समय में यह शहर अपने मूल आकार से तीन गुना बढ़ गया था। मार्को पोलो ने अपने यात्रा वृत्तांत में "एटजीना" के नाम से इस शहर का जिक्र किया था। मंगोलों के शासन में स्थानीय ट्यूट लोग 10 सालों तक शांति से रहे। फिर 1372 ईस्वी में मिंग साम्राज्य ने इस पर कब्जा कर लिया। किसी को भी नहीं पता कि इस शहर का पतन क्यों हुआ। स्थानीय कहानियों के अनुसार चालाक मिंग राजाओं ने शहर में पानी के एकमात्र स्रोत, एजिन नदी का मार्ग बदल दिया। यह नदी खारा खोटो शहर के बाहर से बहती थी। इसके बाद मिंग राजाओं की फौज ने शहर को घेर लिया। जनता के पास दो ही विकल्प थे, या तो प्यासे मर जाए या सैनिकों से लड़ें। कहते हैं कि, मंगोल सेनापति खारा बातोर इस स्थिति से इतना त्रस्त हो गया कि, अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या करके उसने आत्महत्या कर ली। एक अन्य कहानी है कि, सेनापति खारा बातोर शहर की चार दीवारी के उत्तरी पश्चिमी कोने को तोड़कर भाग गया। मिंग सैनिकों ने ना केवल शहर के सभी लोगों को मार डाला बल्कि मवेशियों और घोड़ों को भी काट दिया। इसके बाद खारा खोटो उजड़ गया। बीसवीं सदी के आरंभ में रूसी खोजी यात्री, प्योत्र कुज्मिक कोज़लवोव के नेतृत्व में हुई मंगोल शिचुआन खोज यात्रा में शहर का पता चला। इस खोज के दौरान ट्यूट भाषा की 2000 किताबें और पांडुलिपियाँ, तथा एक स्तूप में बौद्ध धर्म की मूर्तियाँ और लकड़ी की कलाकृतियाँ मिलीं। यह सारा खजाना सेंट पीटर्सबर्ग भेज दिया गया। बाद में हुई खोजों में कई किताबें रोजमर्रा की वस्तुएं, धार्मिक कलाकृतियाँ आदि भी मिलीं।

शिवसेना के बागी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
किसी अन्य पार्टी में विलय नहीं करते, अयोग्यता लागू होती है। आज तक विलय नहीं हुआ, उन्होंने स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ी है।

संविधान के तहत, उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में स्पीकर की शक्ति होती है और ऐसे मामलों पर निर्णय ले सकता है। अविश्वास प्रस्ताव विद्रोहियों द्वारा एक अनधिकृत ईमेल पते के माध्यम से भेजा गया था।

महाराष्ट्र में सियासी घटनाक्रम गहराता ही जा रहा है। इस बीच खबर है कि राज्य में सरकार बनाने के लिए भाजपा भी सक्रिय हो गई है। पहले भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के बीच मुलाकात की खबरें सामने आई थीं। अब खबर है कि शनिवार देर रात असम के मंत्री अशोक सिंघल भी शिवसेना के बागी विधायकों से मिलने गुवाहाटी के रैडिसन ब्लू होटल पहुंचे। इन सबके बीच असली शिवसेना को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। शिंदे गुट की ओर से बालासाहेब के नाम पर अगल पार्टी का मामला चुनाव आयोग तक पहुंच सकता है।

एकनाथ शिंदे द्वारा ट्वीट किए गए वीडियो में बागी विधायक भरतेश गोगावाले ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 2.5 साल में उन शिवसेना विधायकों के साथ बैठक नहीं की, जो 2019 में विधानसभा चुनाव हार गए थे। इसके विपरीत राज्य के डिप्टी मुख्यमंत्री ने 2019 के विधानसभा चुनाव हारने वाले एन.सी.पी. उम्मीदवारों को धन दिया।

बोरिस जॉनसन की तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नजर

लंदन, 26 जून (वार्ता)। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि वह कंजर्वेटिव सांसदों द्वारा हटाये जाने के खतरे के बीच 2030 में तीसरे कार्यकाल की सेवा पर सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं।

जॉनसन ने रंबाडा के किंगाली में राष्ट्रमंडल प्रमुखों की बैठक के अंतिम दिन कहा कि सरकार एकजुट होने और स्तर बढ़ाने की एक विशाल परियोजना पर काम शुरू करेगा।

अगले चुनाव में क्या वह कंजर्वेटिव का नेतृत्व करेंगे के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हां, मैं जीतूंगा, मैं तीसरे कार्यकाल के लिए सक्रिय रूप से सोच रहा हूँ, तब क्या हो सकता है। जब मैं इसे प्राप्त करूंगा तो इसकी समीक्षा करूंगा।

स्काई न्यूज के अनुसार प्रधानमंत्री को आशा है कि उनकी रंबाडा यात्रा से पूर्वी अफ्रीकी देश सकारात्मक ढंग से प्रभावित होंगे। क्योंकि ब्रिटेन में शरण चाहने वालों को वहां से स्थानांतरित करने की सरकार की विवादस्पद योजना को काफी विरोधों का सामना करना पड़ा था। रिविचार को जॉनसन जी 7 सम्मेलन में और मंगलवार से स्पेन में नाटो की बैठक में भाग लेंगे।

'लोकसभा...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
का कहना है कि संगरूर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में उन्हें जीत मिली है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के लिए यह जीत काफी अहम है।

प्रदेश में पिछले छह दिनों से रोज सौ से अधिक नए कोरोना संक्रमित मिले रहे हैं

राज्य में रविवार को 161 नए संक्रमित मिले, इससे पहले शनिवार को 122 रोगी पाए गए थे

—कार्यालय संवाददाता—
जयपुर, 26 जून। प्रदेश में पिछले छह दिनों से नए कोरोना संक्रमितों की संख्या सौ से ऊपर बनी हुई है। इस दौरान राज्य में रविवार को भी थोड़ी और वृद्धि के बाद 161 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं रिकवरी कम होने से एक्टिव केस बढ़कर साढ़े आठ सौ के पार हो गए हैं। प्रदेश में नए कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। इसके चलते रविवार को 13 जिलों में 161 नए संक्रमित मिले हैं। हालांकि इस बीच शनिवार को 122 रोगी पाए गए थे। इधर राजधानी जयपुर में भी पिछले चौबीस घंटों में नए संक्रमितों की संख्या में लगभग दोगुना वृद्धि हुई है। इस दौरान जिले में 66 नए रोगी सामने आए हैं। इसके अलावा जोधपुर में 24, बीकानेर

2.35 लाख आयकर दाता किसान उठा रहे हैं किसान सम्मान निधि

नई दिल्ली, 26 जून। उत्तर प्रदेश में किसानों की इनकम टैक्स रिटर्न की जांच में पता चला है कि, करीब 2.35 लाख किसान सरकार को धोखा देकर फर्जी तरीके से किसान सम्मान निधि उठा रहे हैं। ये किसान आई.टी.आर. चुकाने वाले हैं मगर मुफ्त के सरकारी छह हजार रुपये सालाना मिल रहे हैं तो छोड़े क्यों जाएं। इसी लोभ ने प्रदेश के 2 लाख 35 हजार किसानों को दागी बना दिया।

वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के आयकर रिटर्न खंगाले गए तो उत्तर प्रदेश से अब तक कुल 2

लाख 35 हजार किसान ऐसे मिले जिन्होंने इनकम टैक्स अदा किया और किसान सम्मान निधि भी हासिल की। ऐसा तब किया गया जबकि किसान सम्मान निधि के नियम व शर्तों में यह स्पष्ट किया गया है कि किसान सम्मान निधि उसी किसान को मिलेगी जो भारत का नागरिक होगा, जिसकी खेती होगी और जो आयकरदाता नहीं होगा। अब इन सभी को किसान सम्मान निधि योजना में अपात्र मानते हुए इनसे निधि की अब तक प्राप्त की गई सारी राशि वसूली जा रही है। इन्हें नोटिस जारी किए गए हैं।

हम नामद नहीं इससे पहले भी भड़काऊ बयान देते हुए संजय राउत ने कहा था, आप यहां से गुवाहाटी तक सब कुछ करेंगे और हम अपना गुस्सा भी नहीं निकालेंगे तो कैसा होगा? तो हम क्या नामद हैं, हम नामद नहीं हैं। उन्होंने कहा था, क्या होगा सत्ता चली जाएगी ज्यादा से ज्यादा और क्या होगा? सत्ता जाती है और सत्ता आती भी है।

बागी विधायकों को सुरक्षा वहीं दूसरी ओर, महाराष्ट्र में बागी विधायकों के खिलाफ शिवसैनिकों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए शिवसेना के 15 बागी विधायकों को केंद्र

■ राजधानी जयपुर में सबसे ज्यादा 66 नए संक्रमित सामने आए हैं। इनमें मालवीय नगर में 9, जगतपुरा में 8 जबकि मानसरोवर व वैशाली में 6-6 मरीज मिले हैं।

■ प्रदेश में रिकवरी कम होने से एक्टिव केस बढ़कर साढ़े आठ सौ से अधिक हो गए हैं।

में 22, अलवर में 12, अजमेर में 10, नागौर में 7, भीलवाड़ा, उदयपुर में 6-6, चूरू में 3, झालावाड़ में 2, बांसवाड़ा, जालौर, चित्तौड़गढ़ में 1-1 नए संक्रमित मिला है। हालांकि इस बीच 20 जिलों बारां, बाड़मेर, भरतपुर, बूंदी, देसा, धौलपुर, डूंगरपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, झुंझुन, करौली, कोटा, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सर्वाही माधोपुर, सीकर, सिरोंही और टोंक में कोई भी नया संक्रमित नहीं मिला

‘भारत चौथी औद्योगिक क्रांति का भरपूर लाभ उठायेगा’

म्यूनिख, 26 जून। जी-7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जर्मनी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भारतीय समुदाय को संबोधित किया। यहाँ भारतीयों ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने म्यूनिख में प्रवासी भारतीयों के कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा, "आज 26 जून है जो उस दिन के लिए भी जाना जाता है जब भारत का लोकतंत्र, जो हर भारतीय के डी.एन.ए. में है उसे 47 साल पहले कुचला और दबा दिया गया था। आपातकाल भारत के लोकतंत्र के जीवत इतिहास पर एक काला धब्बा था।"

जर्मनी के म्यूनिख में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछली शताब्दी में औद्योगिक क्रांति से लाभ उठाया। भारत उस समय गुलाम था इसलिए लाभ नहीं उठा सकता था। लेकिन आज चौथी औद्योगिक क्रांति में भारत भी पीछे नहीं रहेगा, अब यह दुनिया में अग्रणी है।

■ इस बीच केन्द्र सरकार ने शिवसेना के 15 बागी विधायकों को वाई कटेगरी की केन्द्रीय सुरक्षा मुहैया कराई है।

■ शरद पवार ने कहा कि, अंत तक हमारा उद्भव ठाकरे को समर्थन जारी रहेगा।

■ शरद पवार ने कहा, महाराष्ट्र में एम.वी.ए. सरकार है और हम इसका समर्थन जारी रखना चाहते हैं। एकनाथ शिंदे और अन्य विधायक सरकार में एन. सी. पी. के साथ थे। पिछले ढाई सालों में उन्हें कोई समस्या नहीं हुई।

सरकार ने वाई प्लस कटेगरी सुरक्षा प्रदान की है। कई जगहों पर

‘प्रधानमंत्री अब फौजियों को नो रैंक नो पैंशन का संदेश दे रहे हैं’

कांग्रेस सांसद दीपेन्द्र सिंह हुड्डा ने कहा कि, अग्निपथ योजना के विरोध में राजस्थान के सभी विधानसभा क्षेत्रों में विधायकों की मौजूदगी में होगा धरना प्रदर्शन

जयपुर, 26 जून (का.प्र.)। कांग्रेस अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग करते हुए 27 जून को पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने जा रही है और राजस्थान में भी सभी विधानसभा क्षेत्रों में विधायक/विधायक प्रत्याशी और प्रमुख नेताओं के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन और सभाओं का आयोजन होगा।

इससे पहले रविवार को अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग करते राज्यसभा सांसद और कांग्रेस कार्यसमिति सदस्य दीपेन्द्र सिंह हुड्डा ने केन्द्र की अग्निपथ स्कीम में रजिस्ट्रेशन के मुद्दे पर कहा कि देश के नौजवान इसमें रजिस्ट्रेशन कराएं, हमें कोई ऐतराज नहीं है। हम देश के युवा की आवाज उठा रहे हैं। युवा स्वतंत्र हैं। जिसको लगता है कि, केन्द्र सरकार की अग्निवीर स्कीम में यथास्थिति रखी हो। जब पाकिस्तान और चीन दोनों एक होकर टूट फूट वॉर की बात करते हैं, ऐसे समय में रक्षा बजट में भारी कटौती कौन सी देश शक्ति है।

इस मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटोसरा ने कहा कि केन्द्र की अग्निपथ स्कीम में अग्निवीर सैनिकों की पत्नी रोकने और रोल बैक की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी देशभर

■ उन्होंने कहा कि, कांग्रेस पूरे देश भर में सभी विधानसभा क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन करेगी।

संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बहुत से नौजवान इस स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। देश में बेरोजगारी का यह आलम है कि बहुत से नौजवान स्वामाविक तौर पर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। देश में कहीं कोई चपरासी की पोस्ट भी निकलती है, तो पी.एच.डी. तक योग्यता वाले युवा उसमें आवेदन करते हैं। केन्द्र सरकार की आर्थिक नीतियों और सत्ता के कारण देश के युवाओं की ये हालात हैं। ऐसे में उस बात से सरकार को स्कीम को सफलता का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए।

हुड्डा ने कहा केन्द्र सरकार देश के किसी भी छोटे गांव-कस्बे में चली जाए। हम निमंत्रण देते हैं राजस्थान में भी केन्द्र सरकार आए। मोदी अपना हेलिकॉप्टर सुबह 5-6 बजे उतार दें। राजस्थान हरियाणा में प्रैक्टिस करने वाले युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा। उनसे पूछ

लें क्या यह योजना ठीक है। इससे वो संतुष्ट हैं या नहीं?

हुड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार सेना में पैंशन रोकने के लिए अग्निपथ स्कीम लाई है। हरियाणा में रेवाड़ी की वीर भूमि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन रैंक, वन पैंशन का नारा दिया, लेकिन अब दिल्ली से नो रैंक नो पैंशन का संदेश फौजियों में दिया है, जो नैगटिव है। एन.डी.ए. सरकार के रक्षा बजट में पिछले 5 साल में बड़ी कटौती हुई है। साल 2017-18 में रक्षा बजट 17.8 फीसदी था। 2020-21 में यह घटकर 13.9 फीसदी रह गया। इतनी भारी गिरावट तब हुई है, जब चीन हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। कई-कई किलोमीटर अंदर तक चीन की फौज चली गई। जब सरकार और फौज ने खुद देश के सामने यथास्थिति रखी हो। जब पाकिस्तान और चीन दोनों एक होकर टूट फूट वॉर की बात करते हैं, ऐसे समय में रक्षा बजट में भारी कटौती कौन सी देश शक्ति है।

इस मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटोसरा ने कहा कि केन्द्र की अग्निपथ स्कीम में अग्निवीर सैनिकों की पत्नी रोकने और रोल बैक की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी देशभर

कांग्रेस प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि, सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ता प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन करेंगे

अग्निपथ के खिलाफ कांग्रेस ने 20 राज्यों में प्रैस कॉन्फ्रेंस की

कांग्रेस प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि, सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ता प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन करेंगे

नई दिल्ली, 26 जून (वार्ता)। कांग्रेस ने अग्निपथ योजना को देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक बताते हुए इसे युवाओं के साथ धोखा करार दिया और कहा कि यह फैसला सेना का नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के जनविरोधी तैयारी का परिणाम है।

कांग्रेस प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल रविवार को यहाँ पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस इस फैसले का कड़ा विरोध कर देशभर में युवाओं को बता रही है कि सरकार उनके साथ धोखा कर रही है। देश के 20 राज्यों की राजधानियों में आज एक साथ संवाददाता सम्मेलन कर सरकार को इस नीति के खिलाफ युवाओं को जागृत किया जा रहा है और पार्टी प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर युवाओं को

■ गोहिल ने कहा कि, अग्निपथ योजना सेना का फैसला नहीं है। यह जबरदस्ती सेना पर थोपा गया है।

जगाने का काम कर रहे है और इसी क्रम में सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ता देश के हर विधानसभा क्षेत्र में अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे।

प्रवक्ता ने कहा की अग्निपथ योजना सेना का फैसला नहीं है, यदि सेना यह निर्णय लेती तो दो साल से चल रही सेना में भर्ती की प्रक्रिया पहले ही रोक दी जाती और युवाओं को नई

योजना के तहत सेना में शामिल होने के लिए कहा जाता।

सेना युवाओं के साथ धोखा नहीं कर सकती है इसलिए सरकार ने जब देखा कि पूरे देश में इस योजना का विरोध हो रहा है तो उसने सारा जिम्मा सेना पर थोपा दिया।

उन्होंने कहा कि पूर्व सी.डी.एस. जनरल बिपिन रावत ने भी कहा था कि सेना में अनुभव महत्वपूर्ण होता है इसलिए एक सैनिक को 58 साल की उम्र में सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए लेकिन मोदी सरकार अपने ही द्वारा नियुक्त सी.डी.एस. की भावना के खिलाफ निर्णय ले रही है।

राहुल गांधी ने...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
होगा कि सचिन पायलट अपने ऊपर हुए इस हमले का जवाब देते हैं या फिर हमेशा की तरह चूपी साध कर धैर्य का परिचय देते हैं।

यहाँ राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोट राहुल गांधी से ई.डी. की पूछता समाप्त होने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कार्यालय में हुई राहुल गांधी की सभा से पहले ही जयपुर लौट आए थे, जबकि उस दिन पूरे देश के सांसद विधायकों सहित प्रमुख नेताओं को वहाँ मौजूद रचना था।

इतना ही नहीं इस कार्यक्रम के लिए विशेष तौर पर मुख्यमंत्री एक दिन पहले ही रात को जोधपुर से दिल्ली गए थे। उस घटनाक्रम से पहले ऐसा क्या हुआ कि लगातार चार दिन दिल्ली में सक्रिय रहने वाले मुख्यमंत्री राहुल गांधी का भाषण सुने बिना ही जयपुर लौट आए। उनके लौटने के बाद उसी सभा में राहुल गांधी ने धैर्य की बात करते हुए सचिन पायलट का उदाहरण भी दिया।

ऐसे में शनिवार को सीकर में मुख्यमंत्री ने जिस तरह से सचिन पायलट का नाम लेकर आरोप लगाया है, उसे लेकर कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने सचिन पायलट के धैर्य को तोड़ने के लिए तथा राहुल गांधी को गलत साबित करने के लिए ही इस तरह का बयान दिया है।

अब 27 जून को जब सचिन पायलट राजस्थान में अपनी विधानसभा क्षेत्र में होंगे, तो देखना यह होगा कि वे किस भाषा में मुख्यमंत्री की ओर से लगाए गए आरोपों का जवाब देंगे या फिर राहुल गांधी को सही साबित करते हुए एक बार फिर धैर्य रखेंगे हैं। हालांकि इस बार यह काम इसलिए मुश्किल हो सकता है कि पहली बार नाम लेकर उन्हें मुख्यमंत्री की ओर से आरोप लगाया गया है तो वहाँ मुख्यमंत्री के नजदीकी नगरीय विकास मंत्री शांति भारीवाल की ओर से उस बयान का समर्थन किया गया है।

इसका मतलब यह भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री खेमा इस लड़ाई को खत्म करने के मूढ़ में नहीं है।